

अपने पौन घंटे के भाषण में राहुल गाँधी ने समां जरूर बांधा संसद में

राहुल ने ये संकेत भी दिये कि, "लीडर ऑफ ऑपोज़िशन" की भूमिका में पूरी तरह से आक्रामक तो रहेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जुलाई। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गाँधी ने अपने पहले भाषण में ही छक्का लगा दिया। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री सहित पांच वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों ने उनका विरोध करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। आज राहुल गाँधी "एंग्री यंग मैन" के अपने नए अवतार में नजर आए, जहाँ उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, ना तो प्रधान मंत्री, ना ही उनकी सरकार और ना ही स्पीकर को, वो लगातार इन पर बार करते रहे।

राहुल गाँधी ने भाजपा समर्थक तथा भाजपा विरोधी ताकतों के बीच गहरी खाई पैदा करके एक नैटिव सैट कर दिया है जिसका अब भाजपा को अनुसरण करना ही होगा। राहुल गाँधी ने अपने मूल बोट बैंक, दलित, पिछड़ों किसानों, गरीबों और मजदूरों, छोटे और मध्यम दुकानदार और उद्यमियों, महिलाओं के अलावा मणिपुर, अग्निवीर, नोटबंदी, जी.एस.टी. के मुद्दे उठाए और कहा कि, कैसे इनका

■ पर, क्या वे इस भूमिका को आगे भी पूरी तरह चला पायेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से पाँच वरिष्ठ मंत्री, जिनमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, खड़े हुए, राहुल के भाषण में उठाये गये मुद्दों और आरोपों का जवाब देने के लिये।

■ इन वरिष्ठ नेताओं ने एक अभियान सा चलाया राहुल के खिलाफ और यह आरोप लगाया राहुल पर कि, वे संपूर्ण हिन्दू समाज को हिन्दू आंतकवादी, देशद्रोही तथा हिंसा में विश्वास रखने वाला मानते हैं।

■ राहुल ने संसद में यह दस्तक तो दे दी कि, "एंग्री यंग मैन" संसद में आ पहुँचा है, पर, राहुल के लिये आगे की राह बहुत लम्बी है।

उपयोग अडानी व अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।

उन्होंने भाजपा और आर.एस.एस. पर, उनके हिन्दुत्व व हिन्दुवाद को लेकर भी हमला बोला। राहुल गाँधी ने कहा, भाजपा तथा प्रधानमंत्री का हिन्दुत्व, हिंसा और नफरत से भरा है तथा वो इसका उपयोग अल्पसंख्यकों को लक्ष्य बनाने के लिए

करते हैं।

उन्होंने कहा, मोदी ने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है, जिसे अब खत्म करना होगा। हमला जारी रखते हुए राहुल गाँधी ने महंगाई, बेरोजगारी, नीट में भ्रष्टाचार और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने तथा कई अन्य मुद्दे उठाए।

रोचक है कि, भाजपा ने राहुल गाँधी के विरुद्ध भारी अभियान छेड़

दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि राहुल गाँधी के अनुसार सभी हिन्दू आंतकवादी, राष्ट्रविरोधी हैं तथा हिंसा में विश्वास करते हैं।

कांग्रेस का कहना है कि, भाजपा झूठ फैलाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए जानी जाती है और बार-बार ऐसा होता रहा है।

सार यह है कि, एक घंटा पैतालीस मिनट के राहुल गाँधी के भाषण के बाद, वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो परिपक्व हो चुका है, भाजपा का सामना करने के लिए तैयार व तत्पर है। बोलते समय आत्मविश्वास से परिपूर्ण राहुल गाँधी ने स्पष्ट कर दिया है कि, विपक्ष के नेता के रूप में वो सभी विपक्षी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ न्याय करेंगे।

यह राजनीति के एक नए ब्रेण्ड की शुरुआत है, जिसे राहुल गाँधी को बरकरार रखना होगा, अब जबकि, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन देश के राजनीतिक मंच पर एंग्री यंग मैन के युग की शुरुआत हो गई है।

विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने मु.मंत्री से मुलाकात की

जयपुर, 1 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को उनके आवास पर वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ राजस्थान में सड़क, जल, बिजली, नगरीय विकास और परिवहन क्षेत्र के विषयों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के विकास में वर्ल्ड बैंक की भूमिका को लेकर भी विस्तृत चर्चा

■ मुख्यमंत्री के आवास पर हुई चर्चा में मु.मंत्री भजनलाल ने उन्हें राजस्थान में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी।

हुई। भजनलाल शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल के साथ राजस्थान में चल रही परियोजनाओं एवं विभिन्न सेक्टर में किए जा रहे विकास कार्यों सहित भविष्य के विज्ञान की जानकारी साझा की। इस 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में भावना भाटिया, अनंन बंधोपाध्याय, रीनु अनेजा, तुषार अरोड़ा, राजगोपाल और हर्ष शामिल थे।

राहुल गांधी व भाजपा के बीच नोंक-झोंक ऊंचे स्तर की थी, पर अनिर्णित रही

राहुल ने पुरजोर ढंग से अपने भाषण में कहा कि, जो अपने आपको हिन्दू कहते हैं, चौबीस घंटे "हिंसा व घृणा" फैलाने में जुटे रहे हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जुलाई। राहुल गाँधी ने विपक्ष के नेता की भूमिका में अपने पहले ही भाषण में आज आर.एस.एस.-भाजपा के हिन्दुत्व ब्रेण्ड से सीधी टक्कर लेने का विकल्प चुना। उन्होंने सतारूढ़ पार्टी की लोकसभा में प्रत्यक्ष आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं, वे चौबीस घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भारी शोर-शरावा किया और प्रधानमंत्री ने भी इस पर जोर दिया कि संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। गांधी के पलटवार करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) या मोदी ही संपूर्ण हिंदू समाज नहीं है। कांग्रेस नेता ने भगवान शिव का एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ प्र.मंत्री मोदी ने जवाब में तुरन्त कहा कि, पूर्ण हिन्दू समाज को "हिंसात्मक" कहना गंभीर बात है।

■ राहुल ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं संपूर्ण हिन्दू समाज की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। राहुल ने भगवान शिव का चित्र लहराते हुए कहा, इनका मैसेज है, अहिंसा और कभी नहीं घबराने का।

■ मुझे गर्व है कि, मैं शिव भक्त हूँ तथा घबराया नहीं, जब मुझ पर बीस से अधिक मुकदमे दायर किये गये, मेरा घर ले लिया गया और ई.डी. ने 55 घंटे सख्त पूछताछ की।

■ राहुल ने यह भी कहा कि, वे खुश हैं कि, वे विपक्ष में हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिये "पावर" से बड़ी एक और चीज है और वह है "सत्य"।

■ फिर राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिड़ला पर आक्रमण किया, यह कह कर कि, वे मोदी समक्ष झुके क्यों? ओम बिड़ला ने जवाब दिया कि, संस्कृति यह सिखाती है कि, बड़ों के सम्मुख झुकना चाहिये।

कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा

कांग्रेस हाईकमान की सिद्धारमैया और शिव कुमार को दो टूक सलाह, सरकार चलाने पर फोकस कीजिए

-लक्ष्मण बैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जुलाई। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह पर सख्त रुख अपनाया है और सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की सभी चर्चाओं को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया एवं उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार कुछ दिन पूर्व दिल्ली गए थे। कहा जाता है कि उन्हें वहाँ सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने मतभेद सड़क पर ले जाने की बजाय आपस में सुलह कर लें।

एक ऐसे समय में जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन के बल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपने को पुनःस्थापित कर रही है, सम्झा जाता है कि पार्टी ने कर्नाटक के पार्टी नेताओं से कहा है कि वे किसी भी रूप में नेतृत्व के मुद्दे पर अधिक दबाव नहीं बनाएँ और दोनों नेताओं को आपस में सुलह करने की सलाह देकर वापस प्रदेश भेज दिया।

वापस आने के बाद, जब मीडिया के लोगों ने जोर देकर मुख्यमंत्री

■ कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक इकाई की अंतर्कलह पर सख्ती दिखाई और नेतृत्व परिवर्तन की सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया।

■ कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से कहा है कि, वे सारे मतभेद भुलाकर सरकार चलाने पर ध्यान दें, अपनी लड़ाई सड़क पर न ले जाएं।

■ ज्ञातव्य है कि, कर्नाटक की कांग्रेस इकाई में चल रही भारी उठापट के चलते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दिल्ली गए थे। जिसके कारण नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें शुरु हो गई थीं।

■ सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के आपसी मतभेदों से भाजपा को भी सरकार गिरने और एन.डी.ए. की सरकार बनाने की उम्मीद थी।

सिद्धारमैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा केन्द्रीय नेतृत्व, हाईकमान के दायरे में आता है और इस प्रकार के मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती है। साफ कहें तो न तो मुख्यमंत्री और न

ही उप मुख्यमंत्री ने अपनी बातों में ऐसी कोई चर्चा का जिक्र किया, परंतु उनके नज़दीकी समर्थक ही इस युद्ध को मीडिया में बयानबाजी के माध्यम से लड़ रहे थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल

नई दिल्ली, 1 जुलाई। मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। ऐक्टिविस्ट को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में यह सजा दी है। मेधा पाटकर पर आरोप था कि उन्होंने उपराज्यपाल के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी की और इससे जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। यही नहीं अदालत ने मेधा पाटकर को आदेश दिया है कि वह 10 लाख रुपये की रकम विनय सक्सेना को दें। यह उनकी

■ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में यह सजा सुनाई है।

मानहानि की भरपाई के लिए होगी। अदालत के फैसले के बाद मेधा पाटकर की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सत्य कभी हराया नहीं जा सकता। हमने किसी की मानहानि का प्रयास नहीं किया। हम सिर्फ काम करते हैं। इस फैसले को हम ऊपर अदालत में चुनौती देंगे। मेधा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

योगी आदित्यनाथ व भाजपा हाईकमान के संबंधों में फिर एक बार भूचाल आया?

हाईकमान योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं हैं, क्योंकि यू.पी. में भाजपा आधे से ज्यादा सीटों पर हारी है

-श्रीरंज ड्डा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 1 जुलाई। हाल ही की दो घटनाएँ इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि कोई चीज पूरी तरह छुपाकर रखी गई है और वह गुप्त बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच के रिश्ते एक बार फिर खराब हो गये हैं।

भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से आधी सीटें भी नहीं जीत पाई है। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि बहुत खराब हुई है, क्योंकि इस स्थिति के कारण पार्टी लोकसभा में बहुमत की सीमा रेखा को स्पर्श करने में विफल रही है। समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के अभियान का प्रभाव पूरी तरह गृह मंत्री अमित शाह के पास था। प्रत्याशियों के चयन से लेकर संसाधनों तथा मैनेज-पावर की व्यवस्था उन्हीं की देखरेख में हुई थी। लेकिन साफ जाहिर है कि पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व असफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करना नजर नहीं आ रहा है।

योगी आदित्यनाथ को घेरने की रणनीति के अन्तर्गत, केन्द्रीय मंत्री तथा अपना दल (सोनेलाल) नेता अनुपिया पटेल ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर इस बात पर चिन्ता जताई है कि ओ.बी.सी. तथा एस.टी./एस.सी. अर्थवर्धियों को "सरकारी नौकरियों के लिये अनुपयुक्त" बताते हुए,

■ पर, योगी समर्थक कह रहे हैं कि, यू.पी. में टिकट वितरण से, चुनाव संचालन तक, सारी जिम्मेवारी अमित शाह के ऊपर थी। पर, हाईकमान, सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे प्र.मंत्री मोदी की छवि पर भी आघात होता है।

■ बल्कि, हाईकमान की रणनीति तो हार के मुद्दे पर, योगी आदित्यनाथ को कोसने की है।

■ इसी रणनीति के तहत, अपना दल नेता व केन्द्र में मंत्री अनुपिया पटेल ने मु.मंत्री योगी को पत्र लिखकर शिकायत की है कि, सरकारी नौकरियों में ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा है, यह कहकर कि, उम्मीदवार सरकारी नौकरी के "लायक" नहीं पाया गया। यह पत्र सार्वजनिक रूप से उजागर करके, मु.मंत्री योगी की स्थिति अटपटी करने का प्रयास किया गया है।

■ मु.मंत्री ने भी तुरंत जवाब दिया तथा गृह मंत्री अमित शाह के लाइले अफसर, दुर्गा शंकर मिश्रा को "एक्सटेंशन" नहीं दिया और मुख्य सचिव पद से हटा दिया तथा अपने वफादार व नज़दीकी अफसर मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना दिया गया है।

उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। पत्र में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि इस अनुचित व्यवहार तुरन्त रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये। ऐसा माना जा रहा है कि पटेल ने यह पत्र भाजपा नेतृत्व की सलाह पर लिखा था। मीडिया में इस पत्र का प्रकाशन मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी ने पलटवार करते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सी.बी.आई. के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट पहुँचे

नई दिल्ली, 1 जुलाई (वार्ता)। आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई) कथित घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दी गई गिरफ्तारी और विशेष अदालत के

■ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सी.बी.आई. द्वारा उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

केन्द्रीय जांच एजेंसी को उन्हें हिरासत में देने के आदेश के साथ ही गिरफ्तारी को उचित बताते की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल बंद आरोपी केजरीवाल को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत सरकार ने ई.आर.सी.पी. को लटकाया, हमने वादा पूरा किया- मु.मंत्री भजनलाल शर्मा

ई.आर.सी.पी. में विराटनगर को शामिल किए जाने पर आयोजित धन्यवाद सभा में मु.मंत्री ने कहा, किसानों की समृद्धि से प्रदेश खुशहाल होगा

कोटपुतली-बहरोड़/जयपुर, 1 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना देश और प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकते। किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती में बदलाव लाना होगा। बदलते हुए जमाने में किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए खेती करनी होगी। शर्मा सोमवार को कोटपुतली-बहरोड़ जिले के ग्राम भांकरा में संशोधित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) में विराटनगर क्षेत्र को शामिल करने पर आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को उन

■ कोटपुतली बहरोड़ जिले के भांकरा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया।

■ मुख्यमंत्री ने कहा कि, कृषि की उन्नत तकनीक सीखने के लिए राज्य सरकार कृषि वैज्ञानिकों व किसानों को विदेश भी भेजेगी।

■ मुख्यमंत्री ने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की तकलीफ जानता हूँ। पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है और हम इसी संकट को दूर करने में लगे हैं।

■ उन्होंने कहा, ई.आर.सी.पी. परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा।

देशों में भेजेगी, जहां पर खेती की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर खेती की जाती है। वहां से खेती के नए तौर तरीके सीख कर हमारे किसान भाई अपनी

उपज बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार बनते ही मात्र 6 महीने के अल्प समय में संकल्प पत्र के 45 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं। इस दौरान किसानों और पशुपालकों को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले किए हैं। गेहूँ की एमएसपी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 2 हजार रुपये अतिरिक्त सालाना देने तथा पशुपालकों को किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसे फैसले किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 80 हजार से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कोटपुतली-बहरोड़ के भांकरा गांव में किसान सभा को संबोधित किया। किसानों की ओर से पार्वती-काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना यानी एकीकृत ई.आर.सी.पी. में विराटनगर को भी शामिल करने के लिए अभिनंदन एवं आभार समारोह रखा गया था। किसानों ने मंच पर मुख्यमंत्री को हल भेंट कर उनका आभार जताया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया।

विचार बिन्दु

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। -धीरूभाई अंबानी

तीन नए कानून - राहत या आफत ?

1 जुलाई 2024 से भारत में न्याय प्रक्रिया से संबंधित तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 25 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति को सहमति प्राप्त हुई थी। ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू हुए हैं। नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर, स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए, अधिक उपयुक्त कानून बनाए जाएं। एक उद्देश्य यह भी था कि न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों में अत्यधिक विलंब को देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सके।

सरकार, नए कानूनों को बहुत प्रगतिशील एवं नागरिकों के हित में बता रही है, वहीं इसका विरोध करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता इन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बता रहे हैं। अब हम नए कानूनों का जनता पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि इन कानूनों को उस समय संसद द्वारा पारित किया गया जब लोकसभा के 146 विपक्षी सांसदों को सदन से निकाल कर दिया गया था। इस कारण, इन महत्वपूर्ण कानूनों पर, जितनी विस्तृत बहस संसद में होनी चाहिए थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। सरकार द्वारा बहुमत के बल पर ये कानून बिना द्विपक्षीय चर्चा के अनुमोदित करा दिए गए।

पहले हम नए कानून के द्वारा जनहित में बनाए गए कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी घटना की जोरो एफ आई आर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित क्यों न हुई हो? 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाना अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे किसी भी थाने द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में कई बार क्षेत्राधिकार के विवाद में कर दिया जाता है।

कुछ छोटे अपराधों में, सजा के स्थान पर सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान अमेरिका के कानून से लिया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रायश्चित्त करने का अवसर प्रदान करेगा। यह भविष्य को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारक कदम कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जो अंडर ट्रायल की तरह जेल में बंद हैं, उन्हें संबंधित अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक तिहाई समय पूरा होने पर उन्हें जेल से रिहा किया जा सकेगा। वर्तमान प्रावधान के अनुसार, प्रस्तावित सजा की आधी सजा भुगत लेना आवश्यक था। इससे जेलों में बंद कई कैदियों को राहत मिलेगी और जेलों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।

कोई गंभीर अपराधों जैसे बालकों के साथ यौन अपराध, बलात्कार, गैररूप आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नैतिकता का आख्यान देकर या शादी के नाम पर धोखे में रखकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

'मोब लिंचिंग' का कोई उल्लेख पुराने कानून में नहीं था। अब इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि आने वाले समय में भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को हत्या करने की घटनाएं कम हों।

न्यायिक प्रकरणों में विभिन्न स्तरों पर निरस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे पुलिस को चार्जशीट, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। बहस सुनने के बाद 15 दिन में फैसला सुनाना होगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार, जहां इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से पूरे देश में पुलिस राज स्थापित हो जाएगा। यह कहने का आधार निम्न है :-

वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने में जाने पर उसकी एफआईआर दर्ज किए जाने की अनिवार्यता पुलिस पर थी। अब यह प्रावधान किया गया है कि पहले शिकायत के रूप में उसे पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा और 15 दिन में उस पर अनुसंधान के पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे कई प्रकार के मुकदमे बढ़ने की संभावना है। इस अवाधि के दौरान यह संभावना भी है कि कई प्रकार के साक्ष्यों को प्रभावित कर दिया जाए अथवा मिटा दिया जाए, जिससे अपराध की गंभीरता बहुत कम हो जाएगी। इस दृष्टि से पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है। जो व्यक्ति पुलिस को स्वार्थ पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसकी एफ आई आर दर्ज करने से मना किया जा सकता है। सत्ता का प्रभाव भी इसमें बहुत काम करेगा।

नए कानून में, हालांकि राजद्रोह के अपराध का प्रावधान हटा दिया गया है, किंतु इसके स्थान पर पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लिखने, बोलने या सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी प्रकार की बात करने पर,

यदि पुलिस यह समझे कि वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो वह संबंधित व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। यह कोई किसी थानेदार द्वारा भी किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि पुलिस किस प्रकार सत्ताधारी दल के इशारे काम करती है। इस प्रावधान का बहुत अधिक दुरुपयोग होने की संभावना है और यह नागरिक के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। पुलिस जिससे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है और नए प्रावधान के अंतर्गत पुलिस रिमांड की समयवधि भी 15 दिन के स्थान पर 90 दिन कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस जिससे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले और 3 महीने तक अपनी हिरासत में रख सकती है। इस बदलाव को प्रतिगामी कदम के रूप में ही देखा जाएगा।

दृश्य श्रव्य साक्ष्य अर्थात् 'ऑडियो विडियो एडिड्स' और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नए कानून में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि, पुलिस जिससे चाहे उसे किसी अपराध की आड़ में गिरफ्तार कर सकेगी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार पुलिस का उपयोग, विरोधियों को गलत मामलों में फंसाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कुछ प्रतिबंधित पदार्थ जैसे ड्रग्स, किसी के घर में रख दिया जाए और बाद में उनका ऑडियो विडियो एडिड्स के द्वारा बना लिया जाए, तो उस व्यक्ति को न केवल गंभीर अपराध में पुलिस हिरासत में ले सकेगी अपितु यह भी संभावना है कि ऑडियो विडियो एडिड्स के कारण उसे सजा भी हो जाएगी। किसी के कंप्यूटर से कोई गैरकानूनी मेल भेजा जाना दिखाया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का मुख्य प्रभाव यह होगा कि नागरिकों में एक भय व्याप्त होगा। वैसे भी हमारी पुलिस बहुत निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए नहीं जानी जाती है। लगभग 90 प्रतिशत व्यक्ति तो अब, डर के भाव ही सरकार के किसी निर्णय की आलोचना करने से बचेंगे। कुछ साहसी व्यक्ति जैसे- पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा करने का प्रयास करेंगे भी, उन्हें सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से किसी न किसी बहाने लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को पुलिस राज ही माना जा सकता है।

पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को कानूनन परिभाषित किया गया है। इसमें भी संबंधित थाने को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह किसी गतिविधि को आतंकवादी गतिविधि मानते हुए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। जो सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस किस प्रकार से किसी भी कानून का दुरुपयोग कर सकती है, इसका नवीनतम उदाहरण अरुणोदय राय के विरुद्ध 14 साल पुराने मामले में यू ए पी ए के अंतर्गत प्रकरण चलाने की दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दी गई स्वीकृति के रूप में सामने आया है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत यह संभावना अधिक बन जाएगी कि जो भी पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे, उन्हें आतंकवादी मानकर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना तब उपयुक्त है जब लोगों का पूरा विश्वास पुलिस में हो और यह विश्वास हो कि वह अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित नहीं करेगी एवं निष्पक्ष रूप से जांच करके अपराधी को सजा दिलवाएगी। इस बारे में राजस्थान के एक पूर्व महानिदेशक ने "अपराधियों में डर, आम जनता में विश्वास" का सूत्र वाक्य दिया था। जब तक ऐसा वास्तव में न हो, तब तक पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

कोलकाता की बार काउंसिल ने नए कानून के लागू होने के विरोध में 1 जुलाई, 2024 को प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था। बार काउंसिल आल इंडिया के अध्यक्ष ने एक परिपत्र जारी किया है कि कोई भी बार काउंसिल का सदस्य इस प्रकार के प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेगा। यह एक प्रकार से चेतावनी है कि यदि कोई प्रोटेस्ट में भाग लेगा तो उसकी बार काउंसिल की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।

नए कानूनों को लागू करने से विभिन्न स्तर पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में लंबित आपराधिक प्रकरणों की कुल संख्या देश में 3 करोड़ से अधिक है। लंबित प्रकरणों पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, इस बारे में अस्पष्टता होने पर न्यायालयों में और प्रकरण बढ़ेंगे, जिसके कारण न्याय समय पर मिलने के स्थान पर और अधिक विलंबित होने की आशंका हो जाएगी।

कई इंटर याचिकाएं इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। अब देखा यह है कि 8 जुलाई, 2024 को जब ग्रीष्मकाश के बाद सर्वोच्च न्यायालय काम करना प्रारंभ करेगा, तब इन याचिकाओं पर उसका क्या दृष्टिकोण रहता है? यदि इन पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तो यह कानून पूरे देश में प्रभावशाली रहेगा। अपेक्षा है कि राज्य की पुलिस कुछ इस प्रकार से काम करे जिसे उसकी छवि में परिवर्तन हो और लोगों का विश्वास पुलिस में पैदा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नए कानून वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होंगे और आम नागरिकों के लिए यह राहत का कारण बनने के स्थान पर उनके लिए एक आफत का कारण ही बन जाएगा।

सरकार स्वयं भी यदि चाहे तो नए कानून के कुछ प्रावधानों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है, जैसा कि उन्होंने जनवरी 2024 में दूक ड्राइवर की देशव्यापी हड़ताल के कारण नए कानून की धारा 106(2) के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस नियम के अंतर्गत किसी भी वाहन चालक के द्वारा दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल से, भीड़ द्वारा 1 घंटाई के डर से, भाग जाने पर, उसे गंभीर अपराध मानते हुए उसे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया।

नए कानूनों को कुछ समय तक स्थगित करने के लिए, कई प्रमुख अधिवक्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने सरकार को प्रतिवेदन भी दिया था, किंतु सरकार ने इन सब की परवाह किए बिना इन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय ले ही लिया है।

यह तो भविष्य ही तय करेगा कि नए कानून आम नागरिक के लिए राहत सिद्ध होते हैं या आफत।

-अतिथि सम्पादक, राजेश भागवत (पूर्व आई.एस. अधिकारी)

होम्योपैथी सर्व सुलभ, भरोसेमन्द तथा बीमारियों का जड़ से नाश करने वाली एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथी के जनक हैनिमेन जी की पुण्यतिथि पर विशेष



प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना

आज पूरे विश्व में 2 जुलाई, 2024 को होम्योपैथी के जन्मदाता क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन जी को एक सौ इक्यासीवीं (181वीं) पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति का अविष्कार किया जो आज होम्योपैथी के नाम से शहर में अपना परचम लहरा रही है। इस पर शहर के वरिष्ठ अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग-अलग प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।

हैनिमेन जी स्वयं एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक थे तथा उन्होंने पाया कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कई व काफी बीमारियों को दवा देती है व रोगी पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता व इनकी दवाइयों के दुष्प्रभाव काफी हैं। इनके दुष्प्रभावों को देखते हुए हैनिमेन

जी ने अपना मन बदला व इससे आहत होकर उन्होंने एक नई चिकित्सा विधि होम्योपैथी का अविष्कार किया तथा उन्होंने अपना सारा जीवन होम्योपैथी पद्धति को ही अर्पित कर दिया। होम्योपैथी के प्रति रोगियों का विश्वास काफी बढ़ा है। होम्योपैथी की तरफ भारत सरकार व आयुष विभाग भी ध्यान दे रहा है। अब होम्योपैथी चिकित्सा का परिणाम गंभीर बीमारियों में भी सुखद व अच्छा आ रहा है। यह चिकित्सा पद्धति चिकित्सक के लिये बहुत मेहनत मांगती है। रोगियों की आपातकाल परिस्थितियों में भी कई बार चमत्कारिक रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का परिणाम काफी अच्छा मिलता है। दुनिया भर में लोग इस पद्धति को काफी महत्व दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयों गंभीर महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माता, बच्चों समेत बुजुर्गों के लिये भी सुरक्षित है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग-अलग प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।

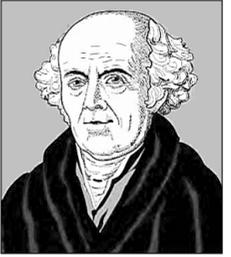
होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय जड़ पकड़ी जब डॉ. जॉन मार्टिन होनिंग बर्गर ने गलेस्वर तंत्रों के पक्षाघात के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉ. होनिंग बर्गर कलकत्ता में रहने लगे और हैजा चिकित्सक के रूप में काफी लोकप्रियता पसक। बाद में डॉ. राजेन्द्र लाल दत्त, डॉ. एम.एल. सरकार जो कि ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे, ने भी होम्योपैथी में प्रेक्टिस करना शुरू किया व डॉ. सरकार ने वर्ष 1868 में प्रथम होम्योपैथिक पत्रिका कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। तदोपरान्त वर्ष 1881 में डॉ. पी.सी. मजुमदार, डॉ. डी.एन. राय व अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक विद्वानों ने मिलकर प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज "कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज" की स्थापना की। राजमर्मा की बीमारियों के लिए यह एक सुरक्षित, आसान व सर्वसुग्राही पद्धति है। लेकिन इसे किसी सुयोग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लेना चाहिए।

होम्योपैथी दवाइयों काफी सस्ती होती है व अन्य पद्धतियों की तुलना में इसका खर्च मात्र 10 से 15 प्रतिशत ही होता है। होम्योपैथी वर्तमान में एक जानी मानी, सर्वाधिक पहचानी जाने वाली महाहृ चिकित्सा पद्धति है। जिसकी शुरुआत 1796 में एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक सेमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमेन ने की थी। जो स्वयं एक मशहूर एलोपैथ थे तथा

एलोपैथी के साइड-इफेक्ट व दुष्प्रभावों की वजह से होम्योपैथी की ओर अग्रसीत हुए व वर्ष 1796 में इसका अविष्कार किया। व प्रचार-प्रसार किया व लोगों में विश्वास जगाया। तथा 10 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर इसे विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा भी इसे काफी सराहा व बढ़ावा दिया जा रहा है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सम, सम्ये, समयति व कांटे से कांटा निकालना इस सिद्धांत पर आधारित है। अतः हर मरीज की बीमारी का इतिहास लक्षणों की आक्रामकता व बीमारी के बारे में जानकर मरीज का इलाज धैर्य पूर्वक शुरू किया जाता है। गंभीर बीमारियों में जैसे फेफड़े, जोड़ों व हड्डी, त्वचा संबंधी यकृत व ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पोलिया रोग आदि में काफी कारगर है। विभिन्न होम्योपैथिक दवाइयों सुप्रशिक्षित चिकित्सक को देखकर ही ही रोग व लक्षणों के आधार पर लेनी चाहिए। ना कि अपने आप से शुरू कर दें। व गंभीर रोग तथा बीमारी का कबू से बाहर हो ही हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाए व सलाह लें। राजमर्मा व दैनिक जीवन की विषम अवस्थाओं में लक्षणों के आधार पर काम में ली जाने वाली दवाएं, नीचे लिखिए कुछ इस प्रकार हैं।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, आचार्य एवं वरिष्ठ होम्योपैथ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर।



होम्योपैथी के जनक, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन।

मेटेलिकम, ब्रायोनिआ एल्बा, पोडो फायलम, चाईना ऑफिसिनैलिस, अर्जेंटम नाईट्रिकम, लाईको पोटैशियम, नक्स चोमिका, बरबेरिस वलोरिस, बेलेडोना, एकोनाईट, अरेनिका मोंटाना, कैफर, सल्फर, सिना, साईलिशिया, थूजा, रसटॉक्स, सीपीया, जेलसिमियम, सैबाल सेरुलेटा, आर्सेनिक एल्बम आदि।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, आचार्य एवं वरिष्ठ होम्योपैथ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नया खतरा



अशोक कुमार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में समाज के लिए कई संभावित लाभ भी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी मदद करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अंधधुंधली और समाचारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कुछ खतरों पर प्रकाश डाला गया है:

अनिर्वाचित बुद्धिमत्ता: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतना बुद्धिमान हो सकता है कि वह मानव नियंत्रण से बाहर हो जाए और अपना खुद का एजेंडा बना ले। यह मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है, गलत सूचना फैला सकता है या यहां तक कि युद्ध भी छेड़ सकता है।

नौकरियों का नुकसान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि मशीनें उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाती हैं जो वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। इससे व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति हो सकती है।

कुछ नौकरियों जिन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें शामिल

हैं: डेटा प्रविष्टि: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम डेटा को मानवों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं।

मैनुअल श्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट पहले से ही निर्माण और भंडारण जैसे उद्योगों में कई कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा: चैटबॉट और वरचुअल असिस्टेंट पहले से ही कई ग्राहक सेवा कार्यों को संभाल रहे हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

परिवहन: सेल्फ-ड्राइविंग कारें और ट्रक टैक्सी ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों और बस चालकों जैसे कई परिवहन कार्यों को स्वचालित कर सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नौकरियों को खत्म करने के साथ-साथ नई नौकरियां भी पैदा करेगा।

कुछ नई नौकरियां जिनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के साथ मांग बढ़ने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित, बनाए रखने और सुधारने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।

डेटा वैज्ञानिक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी।

रोबोटिक्स इंजीनियर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।

नैतिकताविद: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जा रहा है, नैतिकताविदों की आवश्यकता होगी। यह भी संभावना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

हानिकारक तरीके से न किया जाए।

जागरूकता बढ़ाना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा और प्रशिक्षण: लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करने और इसके संभावित खतरों को कम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समाज के लिए गहरा प्रभाव डालने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण का काम करें कि इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाए।

पूर्वाग्रह और भेदभाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम पूर्वाग्रहित हो सकते हैं, जो कुछ समूहों के लोगों के साथ भेदभाव का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित भर्ती प्रणाली कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से खारिज कर सकती है यदि वह अतीत में भेदभावपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित है।

नैतिक दिशा निर्देश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

गोपनीयता का उल्लंघन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य हथियार विकसित करना या साइबर हमले करना। इन खतरों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:-

नैतिक दिशा निर्देश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

नियमन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित और उपयोग करने वाली कंपनियों को विनियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये कानून यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

दुर्भावनापूर्ण उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य हथियार विकसित करना या साइबर हमले करना। इन खतरों को कम करने के लिए

राशिफल मंगलवार 2 जुलाई, 2024



पंडित अनिल शर्मा

आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2081, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 4:40 तक, घृति योग दिन 11:16 तक, बालव करण प्रातः 8:43 तक, चन्द्रमा दिन 11:14 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरु-वृष, शुक-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 4:40 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 8:43 से रात्रि 4:40 तक रहेगा। महापात योग दिन 1:06 से सांय 7:10 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:06 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 2:13 तक, शुभ 3:55 से 5:38 तक। राहकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20

मेष
मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा।
व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।
व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्य-पश्चात व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा।
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदंड रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलेते कार्यों में प्रगति होगी।
स्वनीय कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। दिन के मध्य-पश्चात संभावित खोस से बच पाएंगे।
आय में वृद्धि होगी।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। अटकें हटू कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्य-पश्चात व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।
व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्ययधान सामने आ सकते हैं। दिन के मध्य-पश्चात अटकें हटू कार्य बनने लगेंगे।

तुला
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।
विविधता मामलों से राहत मिल सकती है। अटकें हटू कार्य बनने लगेंगे। दिन के मध्य-पश्चात परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बन रहेगा।
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। दिन के मध्य-पश्चात अटकें हटू कार्य बनने लगेंगे।
विविधता मामलों से राहत मिलेगी।

मकर
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार



Pacific Medical University, Udaipur



(Established by the Rajasthan state legislative assembly by an Act No. 6 of 2014 dated March 04, 2014 & approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956)

DISCOVER YOUR FUTURE WITH PMU

Pacific Medical University brings you a brilliant opportunity to make a career in medical profession. **Enroll Now.**

Take care of those who need the care most.

Take care of your career.

**100%
JOB
ASSURANCE**

**ADMISSION
OPEN 2024-25**



COURSE OFFERED

PACIFIC DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTER

BDS 4 Year
Eligibility : 10+2 in PCB & NEET

MDS 3 Years
Eligibility : BDS & NEET

PACIFIC COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY

B.P.T. 4 Years
Eligibility : 10+2 in (PCB)

M.P.T. 2 Years
Eligibility : B.P.T. with minimum 50% marks

MEDICAL & ALLIED

M.Sc. in Medical 3 Years
• Anatomy • Physiology • Microbiology
• Biochemistry • Pharmacology
Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

M.Phil Clinical Psychology 3 Years
Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

FACULTY OF LIFE SCIENCE

B.Sc. in Clinical Embryology 3 Years
Eligibility : 10+2 Class with PCB

M.Sc. in Clinical Embryology 4 Sem.+
1 Year Internship
Eligibility: B.Sc. in any discipline of Life Sciences, Biosciences, Bachelor's degree in any of Physic, Biological Sciences, M.B.B.S, BDS, BAMS, BHMS, B.Pharma.

TIRUPATI SCHOOL OF NURSING

GNM 3 Years
Eligibility : 10+2 in (PCB)

PACIFIC COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPY

BOT 4 Years + 6 Months Internship
Eligibility : 10+2 in (PCB)

MOT 2 Years
Pediatrics, Neuroscience, Mental Health, Orthopedics, Hand Rehabilitation
Eligibility : Passed BOT with minimum 50% marks

PH.D. & RESEARCH PROGRAMME

Minimum 3 Years
Eligibility : Post Graduation with 55% marks

1. Ph.D. (Medical)
2. Ph.D. (Nursing)
3. Ph.D. (Physiotherapy)
4. Ph.D. (Dentistry)
5. Ph.D. (Clinical Embryology)
6. Ph.D. (Clinical Psychology)
7. Ph.D. (Occupational Therapy)
8. Ph.D. (Paramedical Sciences)

PACIFIC COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES

DIPLOMA Duration : 2 Year
Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology
2. Radiation Technology
3. Operation Theater Technology
4. Cath Lab. Technology
5. Orthopedic Technology
6. Dialysis Technology
7. Emergency & Trauma Care Technology
8. ECG Technology
9. Blood Bank Technology
10. Endoscopy Technology
11. EEG Technology
12. Ophthalmic Technology

BACHELOR Duration : 3 Year + 1 Year
Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology
2. Radiation / Medical Imaging Technology
3. Ophthalmic Technology
4. Operation Theater Technology
5. ECG Technology
6. Endoscopy Technology
7. Emergency & Trauma Care Technology
8. Dialysis Technology
9. EEG Technology
10. Orthopaedic Technology

For More Detail 7877936755

PACIFIC MEDICAL UNIVERSITY, UDAIPUR

Bhilo ka bedla, (Amberi) Udaipur, Rajasthan | Ph. Contact : +91 9672978095, 9587892883

info@pacificmedicaluniversity.ac.in

www.pacificmedicaluniversity.ac.in

फर्जी मार्कशीट मामले में प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी गिरफ्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हुई थी हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा-2022

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी मार्कशीट के मामले में एस.ओ.जी. ने जोधपुर से एक प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर सोमवार को अजमेर स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को चार दिन की रिमांड पर सौंप दिया। एसओजी की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट का सत्यापन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कराना काबूला है। एसओजी अब तक मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जुटी है।



एस.ओ.जी. ने जोधपुर से एक प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर अजमेर स्थित कोर्ट में पेश किया।

एस.ओ.जी. के एडिशनल एसपी मुकेश सोनी ने बताया कि जोधपुर निवासी सोमेश गोदारा और पाली निवासी सुनील बिस्नोई को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सोमवार

को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट मेवाड़ यूनिवर्सिटी से वैरिफिकेशन करवाना सामने आया है, हालांकि एसओजी दोनों से पूछताछ में जुटी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुशील बिस्नोई बजरी का तथा दूसरा

एस.ओ.जी. ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया

पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट का सत्यापन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कराना काबूला

आरोपी सोमेश जोधपुर के एक निजी स्कूल में अध्यापक का काम करता है। उन्होंने मामले में पूछताछ के बाद अन्य गिरफ्तारियों होने की संभावना भी जताई है।

एसओजी के ए.एस.पी. सोनी ने बताया कि एस.ओ.जी. की जांच में सामने आया कि पूर्व में गिरफ्तार डॉ. सुरेश बिस्नोई आरोपी ब्रह्मकुमारी व कमला कुमारी के लिए सत्यापन पत्र बनवाने के लिए बजरी कारोबारी सुनील बिस्नोई से कांटेक्ट में था। ब्लाट्सएस के जरिए ही ब्रह्मकुमारी व कमला कुमारी के उक्त सत्यापन पत्र सहित अन्य दस्तावेज के बारे में ब्लाट्सएस पर चैट की गई। आरोपी ब्रह्मकुमारी को जिस दिन व्यक्तिगत रूप से आयोग ने बुलाया था उसी दिन भी दोनों के बीच कि बसती पानी के खुले होंद में दो हिरण और एक चिकारा की मौत

नीट-यूजी 2024 के संशोधित रिजल्ट्स जारी

रिजल्ट्स में एलन के 23 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक-1

कोटा, (नि.सं.)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सोमवार को नीट-यूजी 2024 के संशोधित रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। इन परिणामों में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की है। एलन के निदेशक डॉ. बृजेश मोहंश्वरी ने बताया कि संशोधित नीट परिणामों में टॉप आल इंडिया रैंक-1 परफेक्ट स्कोर और टॉप-100 में एलन स्टूडेंट्स की संख्या देश में सर्वाधिक है।

महेश्वरी ने बताया कि एनटीए की ओर से जारी संशोधित परिणामों में एलन

के 23 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर प्राप्त कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की है। इनमें 15 क्लासरूम तथा 8 स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग से हैं।

टॉप 100 में 37 स्टूडेंट्स एलन से हैं, जिसमें 27 क्लासरूम तथा 10 डिस्टेंस लर्निंग से एलन से जुड़े हैं। संशोधित परिणामों में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने वाले 15 एलन क्लासरूम स्टूडेंट्स में वेद शिंदे, माजिन मंसूर, रूपायन मंडल, प्राचिता, शैलजा, दिव्यांस, शशांक शर्मा, आर्यन शर्मा, कहकशा परवीन, कृष्णमूर्ति पंकज सिवाल, वेद पटेल, माने नेहा कुलदीप, रितिक राव, तेजस सिंह और अभिनव किसना शामिल हैं। इसके साथ ही तथ्यात अवतार, आरंभीय दाता, इशा कोटारी, उय्यमा मालवारी व मानव प्रियदर्शी एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से तथा आदर्श सिंह, दर्शन पगधर, शिखिन गोयल ने एलन से डिस्टेंस लर्निंग से जुड़कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की।

दो हिरण और एक चिकारा की मौत

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के देगराय ओरण में सोमवार को तीन हिरणों की दर्दनाक मौत हो गई। दो हिरण पानी के खुले होंद में डूब गये, वहीं एक चिकारा हिरण की दीवार से टकराने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से तीनों के शवों को दफनाया। वन्यजीव प्रेमी सुरेशसिंह भाटी ने बताया कि बसती पानी के खुले होंद में दो हिरण डूब गये। वहीं एक चिकारा हिरण के पीछे आवांर कुत्ते भागे। आवांर कुत्ते से बचने के लिए चिकारा हिरण भागा मगर चारों तरफ रिन्यू सोलर कंपनी की दीवार होने के कारण चिकारा भाग नहीं सका और दौड़ते हुए दीवार से टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

सात विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 के सात विषयों एबीएसटी, इंग्लिश, राजस्थानी, एल्गड्ड आर्ट, लाइब्रेरियन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा होम साइंस विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अस्थिती को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।

25 हजार की रिश्वत लेते दो कांस्टेबल गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के खांडाफल्सा थाने के दो कांस्टेबलों को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों कांस्टेबलों ने मुकदमे में मदद के नाम पर मामले में दो कांस्टेबल जैमल राम व कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार को परिवारी से 25 हजार रुपय रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश महेश्वरी ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर एसीबी के उप महानिदेशक हरेन्द्र महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीवसिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप की कार्रवाई कर 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

मुकदमे में मदद के एवज में जांच अधिकारी के नाम पर रिश्वत मांगी थी

मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली की द्वितीय इकाई ने जोधपुर में कार्रवाई कर खांडाफल्सा थाने के कांस्टेबल जैमल राम व कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार को परिवारी से 25 हजार रुपय रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश महेश्वरी ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर एसीबी के उप महानिदेशक हरेन्द्र महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीवसिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप की कार्रवाई कर 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान बत्ती गुल हुई

अजमेर, (कासं)। देश भर में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हुए, जिसको लेकर जवाहर रंगमंच पर सोमवार को संभाग स्तरीय कार्यक्रम



जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े।

देश में लागू हुए तीन नए कानून पर अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे सीएम भजनलाल शर्मा

आयोजित हुआ। कानूनों की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। सीएम शर्मा ने जैसे ही भाषण शुरू किया वैसे ही बिजली चली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए कानून की समापन कर नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव किए गए कानूनों की जानकारी प्रजटेशन के माध्यम से दी

लागू होने को लेकर ही सोमवार को अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर आयोजित हुआ। समारोह में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, कानूनों के जानकार सहित नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि तीन औपनिवेशक काल के कानूनों को समापन कर नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव किए गए कानूनों की जानकारी प्रजटेशन के माध्यम से दी

शर्मा ने कानूनों की जानकारी देने के लिए जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया वैसे ही बिजली गुल हो गई। जवाहर रंगमंच पर मौजूद संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, आईजी लता मनोज, कलेक्टर भारतीय दीक्षित, एसपी देवेन्द्र बिस्नोई सहित अन्य आला अधिकारियों सकेते में आ गए। सीएम के संबोधन के अंतिम क्षण में बिजली आई। वहीं आईजी के संबोधन के दौरान बिजली चली गई। जिससे टाटा पावर की निष्क्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

नये आपराधिक कानूनों के तहत पाली में पहली एफआईआर दर्ज

जयपुर, (नि.सं.)। देश में एक जुलाई से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर (नम्बर 0117) सोमवार को दर्ज की गई।

महानिदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर का सुचारू क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

यह घटना सुबह 7.30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4) एवं 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं बीएनएसएस एवं बीएनएस का सुचारू क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

राई का बाग रेलवे स्टेशन को राईका बाग रेलवे स्टेशन करने की मांग

जोधपुर, (कासं)। राईका समाज सोमवार को प्रशासन की लापरवाही से अपने नाम की खोई पहचान को वापस कायम करने के लिये सड़कों पर उतरा। राईका समाज का आरोप है कि राईका बाग रेलवे स्टेशन जो कि उनके समाज के आसुराम राईका के कारण मिला नाम था, लेकिन वर्तमान सरकार ने राईका बाग रेलवे स्टेशन का नाम राई का बाग कर दिया।

समाज के हजारों लोगों ने मेडिकल कॉलेज चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास इकट्ठा होकर रैली निकाल कर

लालसिंह ने राईका ने बताया कि अब समाज पत्र व्यवहार करने की बजाये ऑनलाइन की राह अपनायेगा जिससे की गुंभी बहरी सरकार इतिहास के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर जागरूक अपनी गलती को सुधार करेगी।

उस पर बनाये बाग का नाम राईका बाग रखा। बरसों से चल रही परम्परा को कुछ साल पहले न जाने किसी के इशारे पर या मानवीय भूल से राईका बाग रेलवे स्टेशन जंक्शन की बजाये राई का बाग स्टेशन कर दिया, जबकि टिकट और रेलवे की ऑनलाइन पर अभी भी राईकाबाग जंक्शन शो किया जा रहा है। राई का बाग को राईका बाग बनाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश से हजारों राईका समाजबंदियों ने आज पत्र परम्परागत वेशभूषा में शामिल होकर अपना प्रदर्शन रेल रैली में शक्ति प्रदर्शन किया।

गोविंद गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन, समाज सेवा, देश सेवा के एक संस्थान रहे : राज्यपाल मिश्र

सामूहिक सद्प्रयासों से विश्वविद्यालय का कायाकल्प होगा : कुलपति ठाकुर

बांसवाड़ा, (नि.सं.)। जनजाति केवल सामाजिक और विषयगत संप्रत्यय नहीं, अपितु एक जीवन-पद्धति और दर्शन है, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समग्र समाज, देश यहां तक की समस्त चराचर जगत के सर्वतोमुखी कल्याण के बीच तंत्र छिपे हैं। इसी जनजाति बाहुव्युषी राजस्थान की भूमि में प्रातः स्मरणीय गोविन्द गुरु के आविर्भाव ने पूरे समाज और देश की दिशा ही बदल दी और सदियों तक जीवन के परिष्कार, कुरीतियों से दूर होने एवं अपना सर्वस्व समर्पित करने के वे जीवन मंत्र दिए हैं जो आज भी न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आज भी सभी को प्रेरणा देते हैं। ये विचार सूत्र राजस्थाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस और विविध कार्यों के लोकार्पण अवसर पर मुख्य अतिथि रूप में व्यक्त किए।

मिश्र ने गोविन्द गुरु और चाण्ड-कांठल क्षेत्र के स्वतंत्रता-सैन्यानि, आंतर शहदों के त्याग और बलिदान प्रति श्रद्धांजलि देते स्पष्ट किया कि गोविन्द गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन, समाज-सेवा, देश-सेवा के एक

राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोविन्द गुरु जनजातीय वि.वि. में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस और विविध कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित

संस्थान रहे जिन्होंने तत्कालीन समय में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, समाज-सुधार, कुरीतियों के उन्मूलन, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और संस्कृतिकरण संरक्षण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। पूरे अंचल में गोविन्द गुरु का योगदान गहरा और व्यापक है। राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय स्थापना दिवस को आत्मवलोकन का

पर्व बताते हुए कहा कि हम अतीत में किए कार्यों का मूल्यांकन करें, भविष्य को पट सक्ती है। हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वर-प्रदत्त संविधान है। हमें जो संरक्षण की पद्धति है, उससे सीख लेने की जरूरत है। जनजातीय क्षेत्र की अपनी परम्पराएँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती आ रही हैं। आज विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि इस संरक्षित धरोहर को सहेजे और

आज भी विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। शिक्षा सभी तरह की दूरियों को पाट सकती है। हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वर-प्रदत्त संविधान है। हमें जो संरक्षण की पद्धति है, उससे सीख लेने की जरूरत है। जनजातीय क्षेत्र की अपनी परम्पराएँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती आ रही हैं। आज विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि इस संरक्षित धरोहर को सहेजे और

विकसित करें। पूरा विश्व आज जल-संकट से जूझ रहा है लेकिन हमारी सनातन जीवन और जनजातीय जीवन पद्धति में पानी को सहेजने की जो पद्धति रही है, उस पर सोच करने की आवश्यकता है। इस दिशा में विश्वविद्यालय विशेष ध्यान देकर जनजातीय संस्कृति, समाज और पारिस्थितिकी संतुलन के सन्दर्भ में विशेष परियोजनाओं पर काम करें। इस अवसर पर कुलपति प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने विश्वविद्यालय की विगत स्थापना से आज तिथि तक हुई विकास यात्रा की बानगी प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने अत्यंत अल्प समय में ही भौतिक विकास, शोध एवं अकादमिक क्षेत्र में पूरे राज्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज

आवश्यकता है कि इसके सर्वांगीण विकास में सभी योगदान करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस पर तीन कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका, पूर्व सांसद कनकमल कटारवाला सांसद निधि मद से बनी कैटीन और विश्वविद्यालय के वित्त से निर्मित सभागार का वरचुअल लोकार्पण किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने माह अक्टूबर में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और पैसिफिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले 75 वें ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस के बोधार् का भी ऑनलाइन विमोचन किया।

कार्यक्रम का संचालन प्रभारी सम्बद्धता डॉ. नरेंद्र पानेरी ने और आभार प्रदर्शन कुलसचिव राजेश जोशी ने किया। कार्यक्रम में राजभवन के सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नगर से पधारे गणमान्य शिक्षाविदों, संस्कृतिधर्मियों, संकाय सदस्यों और इंजीनियरिंग कॉलेज-कैम्पस विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

कार्यालय नगर परिषद मुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
दिनांक :- 27.06.2024

नगर परिषद मुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 15.07.2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा अप्रामांनिक को वेबसाइट <https://eproc.rajjasthan.gov.in> से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://www.sppp.raj.gov.in> पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक DLB24255LOB01870 है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद मुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है। आयुक्त, नगर परिषद मुजानगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीममाल रोड, जालौर दिनांक-25.06.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 03/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रु. 18.35 लाख के 2 सिविल कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु अनिर्दिष्ट प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण डीआईडी/शेड्यूल की वेबसाइट <http://www.dipronline.org>, <http://eproc.rajjasthan.gov.in> व विभागीय वेबसाइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है। 1. NRH2425WSOB00338, 2. NRH 2425WSOB00339

(राज्यीयसिंह कच्छवाह)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर

DIPR/C/5062/2024

कार्यालय नगर परिषद ब्यावर
Tel.No. 01462-258665 Email Add:- npbeawar@gmail.com
दिनांक - 28.06.2024

ई-दर सविदा सूचना
निम्नांकित विवरण के अनुसार ई दर सविदा ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान पर दिनांक 08.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित है। विस्तृत शर्तें ई दर सविदा फार्म के साथ संलग्न है। यह दस्तावेज एस.पी. पोर्टल पर एम्.ई.ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर संलक्ष्य है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोहर राशि	दर सविदा फार्म शुल्क	दर सविदा प्रोसेसिंग शुल्क
1.	COMPUTER OPERATOR SERVICES RATE CONTRACT	30.73 लाख	61.480	1000	500

Nb Code : DLB2425A0622
BID No.: DLB2425SLRC01961
समापति आयुक्त
राज.सं.बा.व/सी/24/1455 नगर परिषद ब्यावर नगर परिषद ब्यावर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
दिनांक-01.07.2024

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए 02 विभागों के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाते हैं। उक्त विभागों के तहत विभिन्न पदों की वैशुलिक योग्यता, पदों की संख्या, वार्षिक वेतन, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अग्रणी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रत्येक विस्तृत विवरण का अवलोकन करी व उक्त विभागों के तहत विभिन्न पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विवरण संख्या, पदों की संख्या, आवेदन आवेदन व अन्य विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	विधान संख्या	पदों की संख्या	आवेदन अवधि
1	कक्षागत विभाग	उप कक्षपाल	04/2024-25	73 (NS&SA)	08.07.2024 से 06.08.2024
2	कक्षागत विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग	उपाचार्य/ज्यूरिफिक ऑफिसियल प्रशिक्षण संयोजक	05/2024-25	36	10.07.2024 से 08.08.2024

अनुप विद्व. व सूचना (राज्यीय) पंजीकृत श्रेणी, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित सूचना हेतु व सूचना के लिए आवेदन को वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षासिद्धि हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सूचनाएं विशेष निदेश तथा सार्वजनिक सेवा निम्नो व्क उपस्थान आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://pssc.rajjasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/संपर्कण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्था रूपायन से -0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

राज निवास मेहता, सचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड पोकरण
दिनांक-25.06.2024

निविदा सूचना संख्या 02/2024-25
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन निर्माण/संरक्षक निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु अनिर्दिष्ट प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है।

ऑन लाईन निविदा निम्नो की पूर्ण तारीख 02.07.2024 से 12.07.2024 तक सायं 6.00 बजे ऑन लाईन निविदा जारी कराने की तारीख 02.07.2024 से 12.07.2024 तक सायं 6.00 बजे निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण वेबसाइट <http://www.dipronline.org> एवं निविदा दस्तावेज का विवरण वेबसाइट <https://eproc.rajjasthan.gov.in> पर एवं <http://sppp.raj.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <https://eproc.rajjasthan.gov.in> पर ऑनलाइन समापित की जायेगी।

NIB CODE PWD2425A0390
PWD2425WSRC01459, PWD2425WSRC01461, PWD2425WSRC01462, PWD2425WSRC01464, PWD2425WSRC01467, PWD2425WSRC01470, PWD2425WSRC01471, PWD2425WSRC01473, PWD2425WSRC01478, PWD2425WSRC01479, PWD2425WSRC01480 (हर्षवर्धन हाथी)

DIPR/C/5102/2024 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड पोकरण

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145-2429971, 2429920

क्रमांक :-MEW/2024-25/37 दिनांक- 28.06.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 07/2024-25
नगर निगम अजमेर की ओर से नगर निगम अजमेर एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों को राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन ईनिविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यों की कुल लागत राशि 40.94 लाख (01 करोड़) ऑनलाइन निविदा प्रथम डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि Date 29.06.24 से 08.07.24 को 6.00 PM तक Technical निविदा खोलने की तिथि व समय Date 09.07.24 को 12.30 PM पर Financial निविदा खोलने की तिथि सकलतम निविदादाता को उचित माध्यम के द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।

विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajjasthan.gov.in> पर एवं नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है। Nib Code :- ANN2425A0404 UBN No. :- ANN2425WSOB00049 राज.सं.बा.व/सी/24/1468 अधिशाषी अभियन्ता

जयपुर विकास प्राधिकरण
सुन्दर साकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दिनांक- 28.06.2024

निविदा सूचना विभाग/अधि.अभि. (मुख्यालय) /02/2024-25
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 'Various renovation and development work at JDA flats Lal Kothi, Malviya Nagar and Sethi colony, JDA, Jaipur for the Year 2024-2025' जिसकी अनुमानित लागत राशि ₹161.84 लाख के लिए ऑनलाइन विडस दिनांक 29.06.2024 को प्रातः 9:30 बजे से आमंत्रित की जाती है। निविदा बोली का ऑनलाइन आवेदन व भुगतान जयपुरा पोर्टल पर करने की तिथि 09.07.2024 को सायं 6.00 बजे तक है। निविदा बोली के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण www.sppp.raj.gov.in, www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं www.jda.urban.rajjasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। (UBN No. JDA 2425WSOB0102)
निविदा में भाग लेने वाले बोलों को निम्न शर्त

खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार को दिए निर्देश

अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्योंहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए

जयपुर, (का.सं.) राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए बनाये गये कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंजान लेते हुए मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कृषि विभाग के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस गृह, एसीएस खाद्य सुरक्षा और एसीएस स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप डंड ने ये आदेश इस संबंध में स्वप्रेरित प्रसंजान लेते हुए दिए। अदालत ने कहा कि, संबंधित अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर नियमित सैपल की जांच करें और हर माह के अंत में अदालत में रिपोर्ट पेश कर इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी दें। अदालत ने कहा कि आज लोग बहुत

- 'राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्तित करें। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करें'
- 'सीएस और कलेक्टर की अध्यक्षता में राज्य व जिला स्तरीय कमेटी का गठन करें। केन्द्र व राज्य सरकार वैबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए'

सी जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त है। ऐसे में हम यह जाने के लिए बहुत कम समय देते हैं कि, जो हम रोज खा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा मानक बिल बनाया गया था, लेकिन उसे अब तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि, सरकार मिलावट

के मुद्दे को गंभीरता से ले, ताकि जीवन बचाया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को त्योंहार या शादी के सीजन तक सीमित नहीं रखा जाए।

अदालत ने मिलावट पर अंकुश लगाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य

स्तरीय कमेटी के साथ-साथ संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा है। अदालत ने जोधपुर और जयपुर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, बार कौंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य वकीलों को कहा है कि वह इस संबंध में अदालत में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की पालना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय व मुख्य सचिव को आदेश की कॉपी भेजी है।

अदालत ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार बीस फीसदी खाद्य पदार्थ मिलावटी या तय मानक स्तर के नहीं हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सर्वे के अनुसार 70 फीसदी दूध में पानी मिला होता है। सर्वे में दूध में डिटजेंट भी मिला है।

अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 समस्या का पूरी तरह

समाधान नहीं करता। अधिनियम असंगठित क्षेत्र, हॉटर्स आदि पर लागू न होकर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट पर ही लागू होता है। इसके अलावा सैपल जांचने की लैब की भी कमी है। तकनीक के अभाव में खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी नहीं रख पाते हैं।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि केन्द्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारी मिलावट को लेकर हाई रिस्क एरिया और समय चिन्तित करें। प्राधिकारी उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला का संचालन सुनिश्चित करें। सीएस और कलेक्टर में खाद्य प्राधिकारी उचित निगरानी का गठन। केन्द्र व राज्य सरकार वैबसाइट बनाए, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों के संपर्क नंबर और टोल फ्री नंबर जारी करें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

'संकल्प पत्र' के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की बैठक ली उपमुख्यमंत्री ने

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने संकल्प पत्र-2023 के क्रियान्वयन के लिए 47 विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार, राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर काम करें। संकल्प पत्र में से 38 बिन्दुओं की पूर्ण क्रियान्विति की जा चुकी है, शेष बचे सभी वादे जल्द पूरे किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द सोमवार को शासन सचिवालय स्थित सभागार में संकल्प पत्र के 9 थीम पर आधारित 343 बिन्दुओं की क्रियान्विति के लिए इनसे संबंधित 47 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रदेश के नवनिर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के ऐसे बिन्दु जिनका सीधा सम्बन्ध नजरिह से है उनको प्राथमिकता देकर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी विभाग प्रशासकीय नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माध्यम से संकल्प पत्र के बिन्दुओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रदेश के वंचित वर्गों सहित आम आदमी के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ सकेगा।

राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई दी



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को जन्म दिन पर श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को फोन कर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने फोन पर राज्यपाल मिश्र के आदर्श व्यक्तित्व और अनुकरणीय बताते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

राज्यपाल के जन्म दिन पर सोमवार प्रातः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें फोन

कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मोदी ने मिश्र के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं में काम करते हुए उन्होंने शुष्ता के साथ आदर्श जीवन मूल्यों को जिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने मिश्र को

जन्म दिन पर पुष्पगुच्छ के साथ श्रीनाथजी की छवि भी उपहार स्वरूप भेंट की और शॉल, दुग्धु ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मिश्र को जन्म दिन पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा सहित देश के विभिन्न राज्यों से मंत्री, सांसद, विधायक एवं विशिष्टजन ने भी फोन कर बधाई दी।

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस का अधिग्रहण किया

जयपुर, (का.सं.) पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कंपनी के एक अग्रणी एफएमसीजी स्पेस में एक मजबूत ब्रांड इन्वैस्टी और देश भर में एक वफादार उपभोक्ता आधार रखती है। इस एचपीसी व्यवसाय में वर्तमान में चर

प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जिनमें डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर और हेयर केयर शामिल हैं। एचपीसी व्यवसाय के अधिग्रहण की यह रणनीतिक पहल कंपनी के मौजूदा एफएमसीजी उत्पाद के पोर्टफोलियो को प्रतिष्ठित ब्रांडों की एक शृंखला के साथ मजबूत करेगी और राजस्व एवं एबिटा की वृद्धि में भी योगदान देगी।

पीएफएल, पीएएल के संपूर्ण व्यवसाय को एक चालू व्यवसाय के आधार पर अधिग्रहित करने के लिये तैयार है, और इसमें व्यवसाय, संबंधित कर्मचारियों वितरण नेटवर्क, अनुबंधों, लाइसेंसों, परमिटों सहमतियों और इस ऑपरेशन के लिये आवश्यक अनुमोदनों से संबंधित सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां शामिल हैं।

एचपीसी व्यवसाय के हस्तांतरण के लिये कंपनी और पीएएल के बीच 1100 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि पर परस्परिक रूप से बातचीत की गई है, जो प्रथागत समायोजन तिथि समायोजन और कंपनी और पीएएल के बीच निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय हस्तांतरण समझौते में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी।

सहकारी समितियां नवाचारों के साथ ग्रामीण जीवन सरल-सुगम बनाएं : गौतम कुमार दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी समितियों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नवाचारों को अपनाया चाहिये, ताकि ग्रामीण जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सके।

दक सोमवार को सहकार भवन में एनसीडीसी के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की पहल पर 54 नये नवाचार हुए हैं। सहकारिता में विकास की अहम संभावनाएं हैं। आज सहकारी समितियां सुपर स्टोर के संचालन के साथ-साथ पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी आदि का संचालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली सहकारी समितियां अपने जिले की अन्य सहकारी समितियों को भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करें एवं उनका सहयोग करें।

सहकारिता मंत्री ने एनसीडीसी के द्विभाषिक पुरस्कार समारोह में चार श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार दिये गये। सर्वश्रेष्ठ वैकल्प श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए पलसाना



सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सोमवार को सहकार भवन में एन.सी.डी.सी. के क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 के पुरस्कार वितरण किये।

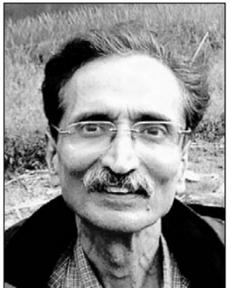
ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीकर को 25 हजार रुपये एवं स्मृति चिन्ह तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अनुपाद को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 हजार रुपये एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ केबीएसएस श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए

बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति, बांसवाड़ा व क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये कोटपूतली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., कोटपूतली तथा सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति की श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिए आपणी सहकारी सेवा समिति लि., माधोराजपुर, क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये

प्रदेश की 8 सहकारी समितियां उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2023 से सम्मानित

महिला सहकारी समिति में केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर, को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति श्रेणी में क्षेत्रीय उत्कृष्टता के लिये सराधाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता के लिये जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार के लिये एक ट्रांफी, स्मृति चिन्ह तथा 25 हजार रुपये का चेक तथा श्रेष्ठता पुरस्कार के लिये एक ट्रांफी, स्मृति चिन्ह तथा 20 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार अर्चना सिंह, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी, विजय शर्मा सहित पुरस्कृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में भजन संध्या आज



जयपुर (कासं)। डॉ. राहुल अग्रवाल की याद में जयपुर के बनीपार्क स्थित बनीपार्क धर्माथ संस्थान में मंगलवार शाम 5 से 6 बजे तक भजन संध्या आयोजित की जायेगी। डॉ. अग्रवाल बेहद संजीवा, लोकप्रिय और समाजसेवी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। वे सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से 'मास्टर ऑफ सर्जरी' विषय के स्वर्ण पदक विजेता रहे। उन्होंने करीब 2 शक तक प्लास्टिक सर्जरी के निःशुल्क शिविर भी लगाए।

डॉ. राहुल अग्रवाल के पिता सतीश चंद्र अग्रवाल जन्मदिन के वरिष्ठ नेता और प्रखर वक्ता थे। वे वर्ष 1977 से 1984 तक दो नौ सीट बेल्स लगा रहे थे। बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। सतीश चंद्र अग्रवाल वर्ष 1977 से 1979 तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रहे।

कैबिनेट की बैठक आज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में कहीं महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में बजट सत्र में किए जाने वाले विधायी कार्य के अनुमोदन, विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों को लेकर विचार किया जाएगा। तबादला नीति के विभागों के अलग अलग प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी।

नये जिलों के पुर्णगठन की रिपोर्ट 15 दिन में देगी हाईपावर कमेटी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने निर्देश दिए कि नए जिलों के पुर्णगठन के लिये गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी 15 दिवस के भीतर सभी व्यवहारिक बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए जिलों के गठन का मूल उद्देश्य राजनीति से प्रेरित ना होकर जहाँत आधारित होना चाहिये। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा सोमवार को सचिवालय में राज्य विभाग के साथ नए जिलों के पुर्णगठन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए जिलों के पुर्णगठन की प्रक्रिया आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या के आधार पर हो।

'टीबी मुक्त' अभियान का तीसरा चरण

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीसर के निर्देशों पर राजस्थान को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

भाजपा विधायक दल की बैठक आज

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही 3 जुलाई से चलेगी। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ बजट पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाए गए सवालों के जवाब भी कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा तैयार करवाए गए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद सदन में पिछली विधानसभा के लंबित सवालों के जवाब भी 3 माह के दौरान पेश करने के लिए पाबंद किया गया है। ऐसे में वर्तमान में सदन में लगाए गए सभी सवालों को जवाब समय पर लगाए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही नहीं चलने के बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके बयान से यह प्रतीत होता है कि उनके पास सदन में चर्चा के लिए कोई विषय नहीं है।

राहुल गांधी का बयान अति निंदनीय : वैष्णव

जयपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिंदगी भर बिना जिम्मेदारी के पावर एंजॉय करने वाले राहुल गांधी ने आज पहली बार जिम्मेदारी का पद ग्रहण करने के बाद भी बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अध्यक्ष पद पर उनका बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और अति निंदनीय है। कांग्रेस और राहुल गांधी का यह पुराना चाल, चरित्र और चेहरा जिसने हमेशा देश की संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को कमजोर किया है। इससे पहले उन्होंने प्रेस क्लब में अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़

घर के बाहर कार में बैठी स्कूल टीचर से दिनदहाड़े लूट

जयपुर। शिपा पथ इलाके में घर के बाहर कार में बैठी प्राइवेट स्कूल टीचर से बदमाश दिनदहाड़े ज्वेलरी लूट ले गए। पुलिस जानकारी में सामने आया है कि रास्ता पछने के बहाने बाइक सवार तीन बदमाश कार के पास आकर रुके। इसमें से एक बाइक से उतरा और कार में बैठी टीचर के पास गया। रास्ता पछने के बहाने पहले तो गले से चेन तोड़ी, हडबडी में चेन कार में ही गिर गई। इसके बाद बदमाश ने कलाई से ब्रेसलेट खींच ली और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि शिपा पथ निवासी सुनीता जैन रविवार दोपहर साढ़े 3 बजे अपने 7 साल के बेटे अयांश के साथ पार्क जाने के लिए कार में बैठी थी। अयांश और मैं दोनों सीट बेल्स लगा रहे थे। तभी बाइक पर तीन लड़के आए। एक लड़का नीचे उतरा और पता पूछने के बहाने कार के पास आया और मेरे गले पर झपट्टा मारा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस जद्दोजूद में चेन टूटकर कार में नीचे गिर गई।

कलचरल सोसायटी के 66 वर्ष पूर्ण हुए

जयपुर (कासं)। राजस्थान की प्रथम पंजीकृत सांस्कृतिक संस्था कलचरल सोसायटी ऑफ राजस्थान ने अपने 66 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। संस्था के महामंत्री सुरेश त्रिवेदी ने बताया कि पिछले 66 सालों में संस्था ने कई तत्कालीन उदीयमान और आज के प्रसिद्ध कलाकारों को मंच प्रदान कर उत्साहित व स्थापित किया है।

मनजिंदर सिंह ने दक्षिण पश्चिमी कमांड की कमान संभाली

जयपुर (कासं)। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने 1 जुलाई 2024 को प्रेरणा स्थल में एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित कर, जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभाली।

ज्ञात रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के छात्र हैं। उन्होंने दिसम्बर 1986 में 19 मद्रास में कमीशन लिया। करीब 37 साल के अपने प्रतिष्ठित और शानदार सैन्य करियर में, उन्हें जम्मू कश्मीर और पश्चिमी मोर्चे पर कमांड और स्टाफ नियुक्तियों का गौरव प्राप्त हुआ है। जनरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर में कांडरट इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अपनी बटालियन की कमान संभाली, नियंत्रण रेखा पर इन्फैंट्री ब्रिगेड, डेजेंट स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में एक इन्फैंट्री डिवीजन और जम्मू कश्मीर में कांडरट इंसर्जेंसी ऑपरेशन में नियंत्रण रेखा पर तैनात कोर की कमान भी संभाली।



लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह

उनकी विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में जम्मू कश्मीर में कांडरट इंसर्जेंसी ऑपरेशन में तैनात कोर में कर्नल जीएस (आईडब्ल्यू) और कमांड मुख्यालय में कर्नल जीएस (ऑप्स/एयर), बीजीएस (ऑप्स), एमजीजीएस (ऑप्स) और सीओएस शामिल हैं। उनकी अनुदेशात्मक नियुक्तियों में भारतीय सैन्य अकादमी में प्लाटून कमांडर और प्रशिक्षक सीएलसी और भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (इन्स्ट्रू), भूटान में डीएस कोआर्ड शामिल हैं।

संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताया है। यह बेहद निंदनीय, दुष्प्रभावी और पूरे हिंदू समाज का अपमान है। 2010 में इनके तत्कालीन मंत्री पी चिंदबरम ने और 2013 में इनके तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को बेहद नीचा किया है। संसद में चर्चा के दौरान हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताया किसी भी तरीके से नेता विपक्ष के लिए शोभनीय नहीं है।

वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह की लोकतांत्रिक सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से नेशनल एडवाइजरी कमेटी के नाम पर सोनिया गांधी चलाती थीं। कांग्रेस वो पार्टी जिसने कमिटेड ज्यूडिशरी की बात की। राहुल गांधी भारतीय संस्कृति से अंधविश्न हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या में मुआवजे पर झूठी और भ्रामक बात कही। 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा दुकानों को जन भागीदारी के तहत रीलोकेंट भी किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज

मंत्री जोराराम ने लॉन्च किए जयपुर डेयरी के 6 उत्पाद



जयपुर। पशुपालन, डेयरी व गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर सरस डेयरी के 6 उत्पाद लॉन्च किए। उन्होंने जयपुर डेयरी द्वारा चलाई जा रही 'उच्च प्रयोगशाला' द्वारा दूध की गुणवत्ता बनाये रखने को महत्वपूर्ण बताते हुए इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा। जयपुर डेयरी द्वारा उरमूल, बीकारनेर के गाय के दूध 'थार अमृत' को लॉन्च करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि उपभोक्ताओं को गाय का दूध और पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना शुद्ध और काम है। गृह एवं गोपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बैदम ने कहा कि राजस्थान में डेयरी विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें तलाशने में सहकारी डेयरियों को महती भूमिका है। प्रमुख शासन सचिव विकास सौताराम भाले ने कहा कि जयपुर डेयरी को गाय के दूध के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त और शुद्ध गाय के घी की लॉन्चिंग करनी चाहिए। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध संचालक सुषमा अरोड़ा कहा कि आने वाले दिनों में सरस के कुछ और प्रोडक्ट्स की भी लॉन्चिंग की जावेगी, जिसमें ऊंटनी के दूध से बने बिस्कुट और केमल मिल्क

पाउडर शामिल है। जयपुर डेयरी अध्यक्ष ओम पुनिया ने डेयरी के 50 वर्षों की विकास यात्रा को उल्लेख करते हुए पिछले कुछ वर्षों के दौरान जयपुर डेयरी की उपलब्धियों को रेखांकित किया और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने मांग की कि गुजरात की अमूल डेयरी के जैसे जयपुर डेयरी के पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिये ताकि वह अपने व्यापार से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। जयपुर डेयरी के प्रबन्ध संचालक मनीष फौजदार ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जयपुर डेयरी द्वारा छाछ के दो नये फ्लेवर पोदीना छाछ और तड़का छाछ की लॉन्चिंग के साथ-साथ आईसक्रीम के तीन नये फ्लेवर वनीला शुगर फ्री, अमेरिकन नट्स और स्ट्रोबेरी की लॉन्चिंग की गई।

इसके अलावा बीकानेर की उरमूल डेयरी के गाय के दूध धार अमृत की भी लॉन्चिंग की गई। उन्होंने कहा कि 250 एमएल छाछ के दो नये फ्लेवर 15 रुपये प्रति पैक दी दर से उपलब्ध होंगे जबकि गाय का 500 एमएल दूध 28 रुपये में और 1 लीटर दूध 56 रुपये में उपलब्ध होगा।

शराब कारोबारी व खनन ठेकेदारों को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश

जयपुर। चित्रकूट नगर थाना पुलिस ने शराब कारोबारी व खनन व्यवसायी को धमकी देकर रंगदारी वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 बदमाशों को दो मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से दो हथियार व 6 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए बडी सफलता हासिल कि है। पुलिस ने पूर्व में भी 14 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस और जेल में अपने अपराधी साथियों के उपयोग में लेने के लिए जेल में फेंकने के लिए खरीदे गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए थे।

पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ के सुपरविजन में कैलाश चंद्र विरनोई अतिरिक्त पुलिस अच्युत प्रथम ने बताया कि बताया कि जयपुर में संगठित आपराधिक गैंग के नाम पर जांच से मारने की धमकी देकर फिरोती मांगने की बढ रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इस पर चित्रकूट थाना पुलिस ने

विशेष टीम के माध्यम से पूर्व में भी 14 आरोपितों को देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस व जेल में फेंकने के लिए खरीदे गए दो मोबाइल फोन बरामद किए थे।

चित्रकूट थाना पुलिस ने अजमेर जेल हाई सिक्युरिटी जेल से प्रोडक्सन वॉरंट पर विक्रम गुर्जर (28) गांव बामडा जोहडा, खण्डेला, सीकर निवासी, मुकेश जाट (26) ढाणी लखावाली, गांव अमरसर, शाहपुरा निवासी, कुलदोण चौधरी (33) इन्द्रा कॉलोनी, सुभाष मंडी, नीमकाथाना को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने पुलिस पृष्ठताछ में बताया कि सीकर संभाग एवं आसपास के इलाकों के ठेके तथा खनन कार्य से जुड़े लोगों को धमकी देने व एक्सटोरशन को प्लानिंग की जा रही है। इस पर आरोपितों की धरपकड़ के लिए वैशाली नगर अधिकारी रविंद्र सिंह व चित्रकूट थाना अधिकारी जहीर अब्बास ,दौलतपुर थानाधिकारी मनीष शर्मा, डीएसटी ईचार्ज गणेश नारायण व तकनीकी टीम का विशेष गठन कर

वैशाली नगर पश्चिम द्वार कार्रवाई करते हुए सोनू सिंह (25) सुरेली, बनेठा, ठोक निवासी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक रिवाल्वर, एक देशी कट्टा तथा 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सोनू सिंह के सहयोगी लोकेश साहू उर्फ मोदी (27) शेरापुर, सर्वाइडमाथोपुर निवासी, गिरधारी मान गांव रानीपुरा, मानावली ढाणी, शाहपुरा निवासी, हंसराज गुर्जर (19) नागकुण्ड भगोवा, गोकुलपुरा, सीकर निवासी, जयसिंह राव (30) दादिया, अराई अजमेर निवासी, कुलदोण वैष्णव (24) आजाद नगर मदनगंज, किशनगढ़ निवासी को गिरफ्तार किया। पुलिस पृष्ठताछ में सामने आया है कि जय सिंह का काम गैंग को वाहन उपलब्ध करवाना था तथा गैंग के अन्य सदस्य चिन्हित लोगों तथा ठिकानों पर फायरिंग करने की योजना थी। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों की योजना को विफल कर दिया।

